संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है, और

(ख) विशेषज्ञों के नाम क्या हैं और वे जैसलमेर में इस प्रयोजनार्थ कब से काम कर रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) और (ख) राजस्थान के मुख्य मंत्री से ऐसा कोई अनुरोध नहीं मिला है ।

लखनऊ, आगरा और कानपुर में एल0 पी0 जी0 वितरण प्रणाली

1679. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री ईश दत्त यादव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तीन तेल कम्पनियों की वर्तमान रसोई-गैस वितरण प्रणाली से उत्तर प्रदेश में विशेषकर लखनड़, आगरा और कानपुर में उपभोक्ताओं को असुविधा हो रही है,

(ख) क्या उपभोक्ताओं को गत तीन महीनों के दौरान इन शहरों में रसोई गेस के प्रति सिलिंडर पर अधिक पैसा देने के लिए बाध्य किया गया है,

(ग) क्या कुछ वितरण उपभोक्ताओं को कम वजन वाले एल0 पी0 जी0 सिलिंडरों की आपूर्ति कर रहे हैं, और

(घ) यदि हां, तो वितरकों के माध्यक से उपभोक्ताओं को समुचित सेवा सुनिश्चित करने और दोषी वितरकों की पहचान करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां सूचीबद्ध देश में वर्तमान एल पी जी उपभोक्ताओं की मांग कमोबेश पूर्णतया पूरी की जा रही है । लखनऊ, आगरा और कानपुर सहित उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होने वाले अस्थायी बैंक लोगों को बढ़ाए गए कार्य-घंटों और अवकाश के दिनों में भरण संयंत्रों के प्रचालन द्वारा एल पी जी आपूर्तियों में वृद्धि करके और समीपवर्ती क्षेत्रों में भरण संयंत्रों से आपूर्तियों की व्यवस्था करके निपटाया जाता है ।

(ख) सितंबर, 95 से नवंबर, 95 की अवधि के दौरान अधिक कीमत लेने की कोई साबित शिकायत नहीं रही हैं ।

(ग) और (घ) भरण संयंत्रों पर एल पी जी सिलेंडरों के वजन की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित पद्धतियां हैं । एल पी जी भरण संयंत्रों से प्राप्त होने पर डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा एल पी जी सिलेंडर तोले जाते हैं और कम वजन वाले सिलेंडर भरण संयंत्रों का वापस भेज दिए जाते हैं । उपभोक्ताओं को रीफिल सिलेंडर की सुपर्दगी से पहले डिस्ट्रीब्यूटरों को इसे तौलना होता है ताकि वजन की शुद्धता सुनिश्चित की जा सके । जैसे ही कम वजन के सिलेंडरों की बिक्री से संबंधित विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं । एल पी जी विपणन कंपनियों द्वारा जांच-पड़ताल की जाती है और यदि शिकायत साबित हो जाती है, तो विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों तथा राज्य सरकारों द्वारा भी अपने माप और तौल विभागों के माध्यम से एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाती हैं । उपभोक्ता से कम वजन वाला सिलेंडर वापस लेकर उसे एक नया सिलेंडर भी जारी किया जाता है ।

Security threat to Egyptian Embassy Staff

1680. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the staff of Egyptian Embassy in India is facing threats of terrorist attacks;

(b) if so, whether any request has been received for providing tight security; and

(c) if so, what action has been taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI R. L. BHATIA): (a) to (c) Under the Vienna Convention on Diplomatic Relations, the Receiving State is under an obligation to take all appropriate steps to protect the premises of the Missions, persons of diplomatic agents and private residences occupied by them against any intrusion, damage, disturbance or impairment. The same protection is also given to non-diplomatic staff members.

The Government of India is fully meeting its obligations on this account and appropriate security is being provided to all foreign diplomatic interests as per the requirements of each

Mission.

मध्य प्रदेश के बीना शहर में तेल शोधक कारखाने

1681. **श्री राघवजी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बीना शहर के पास तेल शोधक कारखाने की स्थापना के संबंध में क्या प्रगति हुई है, और

(ख) क्या यह सच है कि इसके निर्माण में विलम्ब हो रहा है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इसका निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना नहीं, तो इसका निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) और (ख) सरकार ने 1686 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा घटक सहित 5277 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से मध्य प्रदेश में बीना में 6 एम एम टी पी ए क्षमता वाली ग्रासरूट ईंधन/लाब्स रिफाइनरी की स्थापना तथा वाडीनार में सिंगल पाइंट भूरिंग और कच्चे तेल के टर्मिनल सहित संबंधित क्रूड आयात सुविधा एवं क्रास कंट्री पाइपलाइन के लिए मैं0 भारत पेट्रोलियम कापोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव का 11.12.95 को अनुमोदन कर दिया है । परियोजना के सरकारी अनुमोदन की तिथि से 42 महीनों के भीतर यांत्रिक रूप से पूर्ण होन तथा यांत्रिक पूर्णता के बाद छः महीनों के भीतर चालू होने का अनुमान है । चूंकि परियोजना हाल ही में कोई विलंब नहीं है ।

Discussion with the U.S. Official on Regional Arm-Race

1682. SHRI PASUMPON THA KIRUTTINAN: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have discussed the matter in regard to resumption of American aid to Pakistan leading arms race in the sub continent with the U.S. Assistant Secretary during her visit in November, 1995; and

(b) if so, the details of the discussions and the outcome thereof?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) Yes, Sir.

(b) The clear and firm position of Government of India against the proposal to supply sophisticated military equipment to Pakistan through the mechanism of the Brown Amendment, and the strong adverse reaction that this had caused in Indian political and public opinion was reiterated tp the US Assistant Secretary.

The US assessment, which we do not accept, is that the transfer of the $368 million military package to Pakistan would not alter the military balance in the region. The US Government has also stated that they have no intention of trying to dismantle the Pressler Amendment as a whole, or of extending the one-time waived to bring in the F-16 aircraft later.

Supply of Gas to Gas based Plants in Tripura

1683. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 512 given in the Rajya Sabha on 15th March, 1995 and state:

(a) the short term and long term plans to utilise proven gas reserves in Tripura;

(b) whether KRIBHCO had lost interest because of non allocation of 1.3 MMSCMD of gas as recommended by MOF on 31st August, 1992;

(c) whether logistic constraints are more insurmountable than bringing gas from Oman; and

(d) whether ONGC/GAIL have taken any special steps for allocation of gas for industries in backward states like Tripura and special consideration is given to* the gas users, if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND